कब तक उछाला जाएगा राम मंदिर का मुद्दा

मनोज कुमार झा/वीणा भटिया

अयोध्या में राममंदिर के निर्माण को लेकर एक बार फ़िर सुगबुगाहट शुरू हो रही है। संतों-महंतों और संघ परिवार से जुड़े नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं। सबसे पहले बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक और भाजपा के राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने राममंदिर निर्माण को लेकर सरकार की आलोचना की। इसके बाद राममंदिर निर्माण समिति के पूर्व संयोजक रहे स्वामी चिन्मयानंद ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। चिन्मयानंद ने चेतावनी दी है कि अगर इस मसले पर केन्द्र सरकार ने अपना रुख साफ़ नहीं किया तो देश भर के साधु-संत विद्रोह कर देंगे। स्वामी चिन्मयानंद पूर्व भाजपा सरकार में गृह राज्यमंत्री रह चुके हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार से लोगों की यह अपेक्षा थी कि वह अयोध्या में राममंदिर निर्माण के लिये क़ानून बनाएगी, पर इस मसले पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आने के बाद रामभक्तों में निराशा है। स्वामी चिन्मयानंद ने कहा है कि सितम्बर में नासिक में होने वाले साधु-संतों के सम्मेलन में राममंदिर निर्माण के लिये किए जाने वाले आन्दोलन की रूप-रेखा बनाई जाएगी। इसके पहले विनय कटियार कह चुके हैं कि अब तो केन्द्र में भाजपा की बहुमत की सरकार है, इसलिए राममंदिर बनाए जाने को लेकर सरकार को विचार करना चाहिए। इस सवाल पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि जब तक भाजपा को दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलता, तब तक राममंदिर बनाने से संबन्धित क़ानून ला पाना संभव नहीं होगा। उन्होंने राज्यसभा में भाजपा का बहुमत नहीं होने की बात भी कही है। इस पर कटियार ने कहा है कि लोकसभा में तो भाजपा को बहुमत है, वहां सरकार को राममंदिर निर्माण से संबन्धित बिल लाना चाहिए।

भूलना नहीं होगा कि राममंदिर ही वह मुद्दा है, जो भाजपा को केन्द्र की सत्ता में लाने में सबसे ज़्यादा मददगार रहा। नब्बे के दशक में संघ परिवार ने योजनाबद्ध ढंग से इस मुद्दे को उभारा। इसमें कांग्रेस की गलतियों का भी फ़ायदा भाजपा को मिला था। आज कांग्रेस के नेता खुल कर भले ही न कहें, पर मन ही मन यह स्वीकार करते हैं कि अगर राजीव गांधी ने राममंदिर का ताला नहीं खुलवाया होता तो भाजपा इस मुद्दे को आगे नहीं बढा पाती। बहरहाल, यह सभी मानते हैं कि यह राममंदिर का मुद्दा था, जिसने भाजपा को केन्द्र की सत्ता तक पहुंचाया। राममंदिर मुद्दे के आकिटेक्ट लालकृष्ण आडवाणी थे, भाजपा की राजनीति में जिनकी अब कोई भूमिका नहीं रह गई है। पर भाजपा को केन्द्र की सत्ता में लाने का श्रेय आडवाणी को ही दिया जायेगा। आडवाणी ने ही रामरथ यात्रा शुरू की थी, जिसके परिणामस्वरूप देश में जबरदस्त सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ था और जिसकी परिणति बाबरी मस्जिद के ध्वंस के रूप में हुई। इसके बाद गोधरा कांड सामने आया फ़िर गुजरात का नरसंहार । इसने भाजपा को केन्द्र की राजनीति में बहुत ज़्यादा बढत दी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर राममंदिर का मुद्दा भाजपा और उसके पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं उठाया होता तो भाजपा के लिये सत्ता तक पहुंच पाना मुश्किल होता। तब से लेकर आज तक भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने राममंदिर मुद्दे को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर वोट बटोरने का भरोसेमंद जरिया बना लिया है। इस बात को संघ के नेताओं के साथ भाजपा के लोग भी भलीभांति समझते हैं कि अयोध्या में राममंदिर का निर्माण संभव नहीं है, लेकिन जैसे ही चुनावों की आहट सुनाई पड़ती है, वो इस मुद्दे को फ़िर से उछालने लगते हैं।

अभी फ़िर से संघ परिवार के लोग़ों और संतों-महंतों द्वारा जो यह मुद्दा उठाया जा रहा है, उसका संबंध कहीं अक्टूबर में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनावों से तो नहीं है? संतों-महंतों ने राममंदिर निर्माण के लिए आंदोलन का वक्त सितम्बर तय किया है। ऐन चुनावों के पहले सांप्रदायिक लहर फ़ैला कर वोटों के ध्रुवीकरण की ही योजना तो नहीं है यह? ये अलग बात है कि बिहार में भाजपा को इस मुद्दे से ज़्यादा सहायता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वहां लालू-नीतीश अलग तरह के समीकरण बना रहे हैं। फ़िर भी राममंदिर निर्माण का मुद्दा उठाने के पीछे संघ परिवार की मंशा जाहिर हो जाती है।

सवाल है कि संघ परिवार और भाजपा कब तक राममंदिर के मुद्दे को उठाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकती रहेगी? जहां तक आम जनता का सवाल है, उसे इस मुद्दे से कुछ लेना-देना नहीं। लेकिन जब भी यह मुद्दा गरमाता है तो अयोध्या और आसपास के इलाकों में खौफ़ का साया मंडराने लगता है। इसकी वजह है कि लोग़ों ने देखा है कि उन्हें मंदिर-मस्जिद विवाद का क्या खामियाज़ा भुगतना पड़ा। नेताओं को तो उच्च श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। अभी हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई। लेकिन आम जनता हर तरह से असुरक्षित है। दंगे फ़ैलने पर सबसे ज्यादा गरीब ही मारे जाते हैं और जब कई-कई दिनों तक कर्फ्यू लगा रहता है तो गरीबों की दिहाड़ी ही मारी जाती है। उन्हें फ़ाकाकशी का सामना करना पड़ता है।

भूलना नहीं होगा कि संघ और भाजपा ने अयोध्या को साम्प्रदायिक वैमनस्य का प्रतीक बना दिया है। रामलला के मंदिर के नाम से ही देश के अल्पसंख्यक खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यह तो भाजपा नेतृत्व को भी पता है कि अयोध्या में राममंदिर का निर्माण करने के लिए क़ानून बना पाना बहुत आसान नहीं है, भले ही उन्हें पूर्ण बहुमत ही क्यों न मिल जाए अथवा राज्यसभा में भाजपा सदस्यों की संख्या पर्याप्त क्यों न हो। यह मामला अदालत में है और पता नहीं कब तक रहेगा। गौरतलब है कि भाजपा के साथ संघ और संघ परिवार के तमाम लोग इसे आस्था से जुड़ा मामला बताते रहे हैं। वे कहते हैं कि क़ानून इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। पर मौका देख कर वे क़ानून बनाने की बात भी करते हैं, क्योंकि भाजपा ने वादा किया था कि पूर्ण बहुमत के साथ उसकी सरकार बनी तो राममंदिर निर्माण के लिए क़ानून लाया जाएगा।

एक बात को कभी नहीं भूला जा सकता कि जो संत-महंत राममंदिर निर्माण नहीं करा पाने के लिये मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, वे ऐसा सिर्फ़ दिखावे के लिए कर रहे हैं। उद्देश्य एक मात्र यही है कि चुनावों के दौरान इस मुद्दे पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सके और भाजपा को उसका लाभ मिले। जहां तक आलोचना का सवाल है, तो स्वामी चिन्मयानंद ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया है कि अगर अयोध्या और गोधरा कांड नहीं हुए होते तो नरेन्द्र मोदी की कोई पहचान नहीं होती। स्वामी चिन्मयानंद ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी रामजन्मभूमि आंदोलन से नहीं जुड़े थे, लेकिन नरेन्द्र मोदी रामजन्मभूमि आन्दोलन की ही उपज है। उन्होंने यह भी कहा कि गोधरा में अगर रामभक्तों से क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं हुआ होता और गुजरात की जनता ने उसका जवाब नहीं दिया होता तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते और सिर्फ़ मुख्यमंत्री ही रहते। यह बात सच है। पर यह कहना गलत होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी राममंदिर आंदोलन से नहीं जुड़े थे। संघ से जुड़ा हर नेता राममंदिर आंदोलन से जुड़ा था। यह अलग बात है कि वाजपेयी भाजपा का उदार चेहरा माने जाते थे, पर सांप्रदायिक विचारधारा में उदारता और कट्टरता का भेद करना सही नहीं लगता। उस समय संघ के थिंकटैंक माने जाने वाले गोविंदाचार्य ने यह सच कहा था कि वाजपेयी मुखौटा हैं, जिसका खामियाज़ा उन्हें भुगतना पड़ा था। वहीं, जब लालकृष्ण आडवाणी ने उदारवादी मुखौटा पहनना चाहा तो संघ उन्हें बरदाश्त नहीं कर पाया। उन्हें भाजपा अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। आज भाजपा के नेता और विश्व हिंदू परिषद् के तोगड़िया और दूसरे संत-महंत अलग-अलग सुर अलापते हैं। ऐसा वे सिर्फ़ भ्रम पैदा करने के लिये करते हैं। जिस तरह रावण के दस सिर थे, पर वह एक था, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने अनेक चेहरों के बावजूद एक हैं। संघ और भाजपा का एक ही उद्देश्य है सत्ता हासिल करने के लिये लाग़ों की धार्मिक भावनाओं को उभारना। संघ ऐसा करने से बाज़ नहीं आ सकता। बहरहाल, भले ही सरकार अयोध्या में राममंदिर का निर्माण नहीं करा सके, लेकिन बहुसंख्यक हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए वहां भगवान राम के नाम पर एक म्यूजियम बनवाने की योजना जरूर बना रही है।

जयललिता प्रकरण : 19 साल बाद परिणाम शून्य

66.65 करोड़ रुपये की बेहिसाब सम्पत्ति रखने के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जयललिता व अन्य तीन को निर्दोष करार दे दिया है। 19 साल से चल रहे इस ड्रामे पर जस्टिस चिका राचप्पा कुमारस्वामी द्वारा चार मिनट में फ़ैसला सुना दिया। उन्होंने कहा जयललिता की बेनामी सम्पत्ति में अज्ञात स्रोतों से आय 2.82 करोड़ (8 प्रतिशत) ही मिली। क़ानून के तहत बेहिसाब सम्पत्ति कम से कम दस फीसद होनी चाहिए।

जयललिता मामले के विशेष सरकारी वकील बी. वी. आचार्य ने बताया कि जयललिता की ओर से लिए गए कर्ज़ को 24 करोड़ बताया गया है जबकि ठीक से जोड़ने पर यह 10 करोड़ ही है। उन्होंने बताया कि दिये गये ब्योरों को ठीक से जोड़ा जाए तो आय से अधिक सम्पत्ति लगभग 16 करोड़ रुपये होगी जो उनकी आय का 76 फीसदी से अधिक होगी।

बी वी आचार्य की बातों से स्पष्ट है कि किस तरह कर्ज़ को बढा-चढाकर बताकर सम्पत्ति को 10 प्रतिशत से नीचे लाया गया। यह आंकड़ों की जादूगरी का ही परिणाम है कि जयललिता आज ससम्मान दोषमुक्त कर दी गयीं। अब वे मुख्यमंत्री बन चूके हैं। भ्रष्टाचार के इस आरोप व सज़ा के बाद उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग गया था।

जयललिता के दोष मुक्त करार दे दिये जाने के बाद सबसे अधिक खुशी मोदी खेमे में है। मोदी, सुषमा स्वराज आदि शीर्ष नेताओं द्वारा तुरंत ही जयललिता को बधाई दी गयी। जयललिता और मोदी की पहले से भी नजदीकियां रही हैं। भाजपा को दक्षिण में अपने पैर टिकाने में जयललिता उन्हें एक मजबूत आधार देंगी, भाजपा इस बात से आशान्वित हैं। साथ ही लोकसभा में कांग्रेस के बाद 37 सदस्यों के एक विपक्ष को मोदी सरकार अपने साथ लाकर विपक्ष को और कमजोर कर देना चाहती है। साथ ही राज्य सभा में भारी अल्पमत वाली भाजपा को 11 सदस्य जयललिता के सहयोग से मिल सकते हैं। यह सब चुनावी व अल्पमत-बहुमत का जोड़ गणित पूंजीवादी राजनीति का सार है।

इसीलिए जयललिता के बरी होने पर भाजपा बेहद खुश है और सांठ-गांठ को आगे बढ़ा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ़ मोदी के भाषणों का व्यावहारिक परिणाम ऐसा ही निकलता था। कई कांग्रेसी भ्रष्टाचारी चुनाव के मय दल-बदल कर भाजपा में शामिल हो गये थे। कुछ तो बाकायदा मंत्रीमंडल की शोभा बढा रहे हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला यह भी दिखलाता है कि कैसे केन्द्रीय सत्ता अपने पक्ष में फ़ैसला करवाने के लिये अप्रत्यक्ष भूमिका निभाती है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता मात्र एक मिथक है यह फैसला इस बात की भी पुष्टि करता है।

नागरिक

तुर्की-ब-तुर्की / मोहन भागवत को जेड+सुरक्षा

हमारा कहना है-

एक साल पहले तक तो मोहन भागवत को किसी सुरक्षा कवच की जरूरत नहीं थी। अब इस एक साल के मोदी शासन में ऐसा क्या हो गया कि इतना ताम-झाम वाला सुरक्षा कवच पहनना पड़ा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता में अपने बढे हुए दबदबे का एहसास कराने के लिए जनता के सिर पर यह बोझ लादा गया हो?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया होने के नाते मोहन भागवत अपना रूतबा प्रधानमंत्री मोदी से कम नहीं समझते। मोदी तो प्राइवेट जेट लेकर उड़ते हैं, बड़े-बड़े कारों के काफ़िलों में घूमते हैं और लाखों के सूट पहन कर इतराते हैं। भागवत के लिये यह सब कर पाना फ़िलहाल संभव नहीं लगता। लिहाज़ा शानो-शौकत बढाने के लिये इर्द-गिर्द वर्दीधारियों की फ़ौज हो तो मामला कुछ न कुछ जमता है। हालांकि संघ कार्यकर्ताओं को आशंका है कि सुरक्षा के नाम पर उन्हें भागवत से काट दिया जायेगा।

यह भी देखना चाहिये कि केन्द्र में भाजपा की सरकार आने के बाद आखिर भागवत ने ऐसा किया क्या है जो उनकी सुरक्षा इस कदर बढाने की जरूरत पड़ गयी। हिन्दू राष्ट्र और हिन्दुत्व की बातें उन्होंने तेज़ तो की हैं पर ऐसा ही और दर्जनों हिन्दुत्ववादी प्रचारक भी तो करते घूम रहे हैं। 'अपनी' सरकार होने का अभयदान जो है उनके साथ। जाहिर है भागवत ने इन सबसे बढ-चढ कर कुछ और भी किया है। संघ प्रमुख होने के नाते हर हिन्दुत्ववादी गुंडे पर इनका वरद्हस्त होना स्वाभाविक है। साथ ही भविष्य में साम्प्रदायिक उन्माद बढाने को लेकर उनके बहुतेरे कार्यक्रम होंगे ही। लिहाज़ा सुरक्षा कवच जरूरी हो चला।

जिस आक्रामकता के साथ भारत में मुसलमानों को पिछले एक वर्ष में असुरक्षित किया गया है इससे अन्तर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों को भी देश के भीतर से स्वयंसेवक मिलने शुरू हो गये हैं। ये संगठन, प्रचार पाने के लिये, भागवत का अपहरण कर सकते हैं। उस हालत में कंधार दोहरया जा सकता है।

एक दूर की कौड़ी यह भी है कि भागवत ने यह सुरक्षा 'अपनों' के खतरे से बचने के लिये ली हो। जानकारों का कहना है कि अयोध्या मन्दिर, समान सिविल कोड, धारा 370 जैसे कई संवेदनशील मसले ऐसे हैं जिनके लटके रहने से हताशा का मारा कोई हिन्दुत्ववादी भागवत को भी क्षति पहुंचा सकता है। वैसे अजीब लगता है यह देखकर कि शस्त्रों और शाखाओं का दम भरने वाली संस्था का मुखिया चूहे की तरफ़ बिल में दुबक कर भावी जीवन गुजारेगा।